अर्द्ध-विकसित देशों की समस्या
(Problems of Under-developed Countries)

अर्द्ध-विकसित देशों की समस्याएँ निम्नलिखित वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं—

(1) आर्थिक समस्याएँ,
(2) सामाजिक समस्याएँ,
(3) प्रशासनिक समस्याएँ,
(4) राजनीतिक समास्याएँ,
(5) अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ।

आर्थिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देश अनेक आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त हैं, जैसे—

(1) बचत एवं पूँजी-निर्माण की समस्या, (2) निर्धनता का विषैला कुचक्र, (3) उपभोग और घरेलू बाजार की अपर्याप्तता, (4) समुचित आर्थिक रचना का न होना, (5) कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित बाधाएँ, तथा (6) बेरोजगारी।

अर्द्ध-विकसित देशों में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम होती अतः बचत नहीं हो पाती। बचत न होने से पूँजी का वाँछित निर्माण नहीं होता, फलस्वरूप आर्थिक विकास के क्रिया-कलाप गति नहीं पाते। प्रति व्यक्ति आय कम

Scanned by CamScanner

होने से देश में उपभोग की मात्रा कम होती है, परिणामतः घरेलू बाजार का क्षेत्र सीमित रहता है, अन्ततोगत्वा देश की अर्थ-व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। आय कम होने से बचत और पूँजी-निर्माण को आघात पहुँचता है और माँग व उपभोग के कम होने से पूँजी-विनियोग के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह पाता। लघु पैमाने पर उत्पादन कार्य होने से बड़े उत्पादन की बचत सम्भव नहीं हो पाती। समुचित आर्थिक रचना का अभाव इन समस्याओं को और भी विषम बना देता है। आर्थिक संरचना में रेलों, सड़कों परिवहन के अन्य साधनों, चिकित्सालयों, स्कूलों, बिजली, पानी, पुलों, आदि को सम्मिलित किया जाता है। यदि इन साधनों की समुचित व्यवस्था नहीं होती तो आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। कृषि एवं भूमि से सम्बन्धित विभिन्न समस्याएँ अर्द्ध-विकसित देशों को ग्रस्त किए रहती हैं। प्रायः यह देखा गया है कि अर्द्ध-विकसित देश कृषि पर अधिक दबाव, कृषिजोतों के उप-विभाजन व उप-खण्डन, कृषि ऋण, अधिक लगान, सिंचाई साधनों के अभाव, कृषि विपणन की असुविधा, प्रति इकाई कम उपज, सुख सुविधाओं की कमी आदि विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त रहती हैं। आर्थिक विकास अवरुद्ध होने से देश में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो जाती है। अर्द्ध-विकसित देशों में बेरोजगारी के अतिरिक्त अर्द्ध-बेरोजगारी (Under-employment) अथवा अदृश्य बेरोजगारी (Disguised un-employment) की समस्या भी विशेष रूप से गम्भीर होती है।

सामाजिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देश विभिन्न सामाजिक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। आर्थिक विकास की दृष्टि से इन देशों की मूलभूत सामाजिक समस्याएँ निम्नलिखित होती हैं—(1) जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या का निम्न गुण-स्तर होना, (2) सामाजिक और संस्थागत बाधाएँ व रूढ़ियाँ, एवं (3) कुशल साहसियों का अभाव।

अर्द्ध-विकसित देशों की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक समस्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है। एक ओर तो आय और पूँजी का अभाव होता है तथा दूसरी ओर जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आर्थिक विकास के प्रयत्नों को विफल बनाती है। इन देशों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि जनसंख्या-वृद्धि के भार को वहन कर सकें एवं रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध करा सकें। सामाजिक और संस्थागत रूढ़ियाँ व कुरीतियाँ भी देश को आगे बढ़ने से रोकती हैं। इनके कारण जनता नवीन परिवर्तनों और परिस्थितियों को अपनाने से यथासम्भव बचना चाहती है, फलस्वरूप देश में तकनीकी और वैज्ञानिक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता। अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों में साहसी वर्ग का भी अभाव पाया जाता है जबकि यही वर्ग मूलतः उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाने और सक्रियता देने का उत्तरदायित्व वहन करता है। अव्यवस्थित सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक ढाँचे के कारण अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक वातावरण ऐसा नहीं होता जो साहसी वर्ग को आगे लाए, परिणामतः देश की प्रगति धीरे-धीरे होती है।

Scanned by CamScanner

राजनीतिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देशों की प्रमुख राजनीतिक समस्याओं में हम राजनीतिक अस्थिरता, नियोजन के प्रति उदासीनता, श्रमिकों के शोषण व बन्धन आदि को ले सकते हैं। राजनीतिक जागरुकता का अभाव होने से प्रायः दीर्घजीवी राजनीतिक गुट या दल नहीं पनप पाते और शासन-सत्ता में स्थायित्व नहीं आ पाता। यह राजनीतिक अस्थिरता एक ओर तो आर्थिक विकास के लिए दृढ़ और स्थायी नीतियों को अवरुद्ध करती है, दूसरी ओर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को निर्बल बनाती है। अशिक्षित और रूढ़िवादी जनता नियोजन के महत्त्व को स्वीकार नहीं करती। राजनीतिक दृष्टि से अस्थिर सरकारें जनता में नियोजन कार्यक्रमों के प्रति विश्वास पैदा नहीं कर पातीं, फलस्वरूप देश को नियोजन के लाभ नहीं मिल पाते। अर्द्ध-विकसित देश विभिन्न श्रमिक समस्याओं से भी ग्रस्त रहते हैं। प्रायः स्थायी श्रमिक वर्ग की कमी बनी रहती है। रूढ़िवादिता और सामाजिक बन्धनों के कारण श्रम की गतिशीलता नहीं पाई जाती। राजनीतिक जागरुकता के अभाव के कारण श्रमिकों में श्रम-संघों जैसी संस्थाएँ समुचित ढंग से नहीं पनप पातीं। जब देश का श्रमिक वर्ग ही अकुशल, अजागरुक और अशिक्षित हो तो देश के आर्थिक विकास को स्वभावतः गति नहीं मिल सकती।

प्रशासनिक समस्याएँ

अर्द्ध-विकसित देश प्रशासनिक दृष्टि से बहुत अकुशल, अवैज्ञानिक और पिछड़े हुए होते हैं। देश की गरीबी और अशिक्षा जनता में चारित्रिक स्तर को ऊँचा नहीं उठने देती, फलस्वरूप कुशल और ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों की सदा कमी बनी रहती है और राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा निजी हितों को अधिक महत्त्व दिया जाता है। भ्रष्टाचार का दानव देश के आर्थिक विकास का गला घोंटता रहता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिकता की समस्या भी बनी रहती है। अर्द्ध-विकसित देश सभी क्षेत्रों में पिछड़े होते हैं और इन सभी क्षेत्रों का समुचित रूप से विकास करना आवश्यक होता है, लेकिन पूँजी और उत्पत्ति के आवश्यक साधनों के अभाव के कारण यह सम्भव नहीं हो पाता कि सभी क्षेत्रों का सन्तुलित विकास किया जा सके। फलस्वरूप प्राथमिकता की समस्या निरन्तर विद्यमान रहती है। देश के सन्तुलित विकास के लिए विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता का क्रम देना पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ

'गरीब की जोरू सब की भाभी' वाली कहावत अर्द्ध-विकसित देशों पर पूरी तरह लागू होती है। ये देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से तो परेशान ही हैं, लेकिन विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ भी इन्हें दबाए रहती हैं। विकसित राष्ट्र इस प्रकार की प्रतिस्पर्द्धात्मक परिस्थितियाँ पैदा कर देते हैं जिनका अविकसित देश प्रायः समुचित ढंग से सामना नहीं कर पाते और उन्हें अनेक रूपों में विकसित राष्ट्रों का आश्रय स्वीकार करना पड़ता है।

Scanned by CamScanner

अन्य समस्याएं

उपर्युक्त समस्याओं के अतिरिक्त अर्द्ध-विकसित देश और भी अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। अर्द्ध-विकसित देशों में आर्थिक विकास के साथ-साथ मूल्य भी बढ़ते है। यदि यह बढ़ोत्तरी मौद्रिक आय की अपेक्षा कम होती है तब तो कोई समस्या पैदा नहीं होती, किन्तु यदि वृद्धि मौद्रिक आय की अपेक्षा अधिक हो जाती है तो समाज-मुद्रा स्फीति के संकट में फँसने लगता है। दूसरी गम्भीर समस्या विदेशी मुद्रा की होती है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक अनेक साधनों को विदेशों से आयात करना होता है जिसके लिए वाँछित विदेशी मुद्रा नहीं मिल पाती। विदेशी मुद्रा के अभाव में आवश्यक साधनों के आयात को रोकने से आर्थिक विकास की गति अवरुद्ध होने का खतरा रहता है; इसीलिए अर्द्ध-विकसित देशों को सहायता व ऋण के लिए विकसित राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता पूँजी व यान्त्रिक ज्ञान दोनों क्षेत्रों में होती है।

अर्द्ध-विकसित देशों की इन विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न उपायों के अतिरिक्त एक प्रभावशाली और अनुशासित राजकोषीय नीति का महत्त्व सर्वोपरि है। राजकोषीय नीति का अर्थ विकसित अर्थ-व्यवस्था में सबसे महत्त्वपूर्ण यह होना चाहिए कि वह पूँजी-निर्माण और पूँजी की गति को बढ़ाने में सहायक बने ताकि यहाँ स्थाई वृद्धि की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिले। इस उद्देश्य की पूर्ति में प्रभावशाली कर-नीति, सार्वजनिक व्यय-नीति, सार्वजनिक ऋण-नीति और हीनार्थ प्रबन्ध की नीति; बड़ी सहायक हो सकती है जिन्हें आवश्यकतानुसार प्रयुक्त किया जाना चाहिए। प्रभावशाली राजकोषीय नीति अर्थ-व्यवस्था की उन्नति में निर्णायक योगदान कर सकती है।

अर्द्ध-विकसित देशों की एक कठिन समस्या विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित है। इन राष्ट्रों को कृषि, यन्त्रों, खाद्यान्नों, सिंचाई साधनों, खाद, बीज आदि की पूर्ति के लिए बहुत कुछ विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। इन साधनों की उपलब्धि तभी सम्भव है जब या तो निर्यात किया जाए अथवा भुगतान हेतु पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाए। विदेशी मुद्रा के अभाव में आर्थिक विकास अवरुद्ध न हो, इसके लिए अर्द्ध-विकसित राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों से समय-समय पर पूँजी व तकनीकी ज्ञान दोनों रूपों में सहायता माँगनी पड़ती है। कभी-कभी यह सहायता ऋणों के रूप में भी मिलती है। आयात नियन्त्रण व निर्यात प्रोत्साहन के द्वारा भी विदेशी विनिमय की समस्या को हल करने का प्रयास किया जाता है। कभी-कभी अवमूल्यन का सहारा भी लिया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ विदेशी मुद्रा सम्बन्धी सहायता विभिन्न शर्तों पर प्रदान करती हैं।

Scanned by CamScanner